

# आज का समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक हिन्दी साप्ताहिक

हर ख़बर पर पैनी नज़र

वर्ष : 17 अंक : 23

लखनऊ, सोमवार 21 सितम्बर 2026 स 27 सितम्बर 2026 तक

पृष्ठ—8

मूल्य : एक रुपया

## चुनाव आयुक्त को भी एसआईआर में नोटिस

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया में कमाल की बातें सामने आ रही हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आयोग की ओर से नोटिस जारी किया गया। अब खबर है कि देश के चुनाव आयुक्त एसएस संधू को भी आयोग की ओर से नोटिस गया है। यही नहीं देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिश्री के नाम से भी नोटिस जारी हुआ है। बताया जा रहा है कि पूर्व उप प्रधानमंत्री लालेंण आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी का नाम भी सूची में है। देश के जाने माने

वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी का नाम भी उस सूची में शामिल है, जिन्हें किसी न किसी वजह से चुनाव आयोग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। बताया



जा रहा है कि अलग अलग मामलों में नाम की स्पेलिंग में अंतर और पुराने एसआईआर रिकॉर्ड से नाम नहीं होने जैसी वजहों से इन लोगों को नोटिस जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि इन सबके

नाम एसआईआर के पहले चरण के बाद जारी मसौदा सूची में शामिल हैं। लेकिन किसी के नाम में स्पेलिंग गलत है तो किसी का नाम पिछली बार के एसआईआर की सूची से मैच नहीं हो रही है यानी उनकी मैपिंग नहीं हो पाई है। कुछ मामलों में रिकॉर्ड में तार्किक विसंगति का भी जिक्र किया गया है। चुनाव आयोग ने तार्किक विसंगति की एक अलग श्रेणी बनाई है, जिसमें पश्चिम बंगाल में 29 लाख से ज्यादा नाम काटे गए। बहरहाल, दिल्ली में कहा जा रहा है कि नोटिस जाने मतलब यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हट गया है। यह मतदाता रिकॉर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया का हिस्सा बताया गया है।

## 10 सीनियर IAS अफसरों के बदले विभाग

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वरिष्ठ आईएस अधिकारियों के विभागों में फेरबदल करते हुए 10 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। बदलाव में कई महत्वपूर्ण विभागों के दायित्व बदले गए हैं। अमित कुमार घोष वर्तमान में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा थे, अब उन्हें अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा बनाया गया है। अमृत अभिजात अपर मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य के साथ अब परिवहन का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। वी. हेकाली झिमोमी को प्रमुख सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के हटाकर प्रमुख सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा बनाया गया है। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा महेंद्र प्रसाद अग्रवाल अब प्रमुख सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन होंगे। प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार को प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद, प्रमुख सचिव उपभोक्ता मामले तथा आयुक्त

खाद्य एवं रसद बनाया गया है। डॉ. एमकेएस सुंदरम वर्तमान में प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन तथा प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा थे, अब उन्हें प्रमुख सचिव कृषि, प्रमुख सचिव कृषि शिक्षण एवं अनुसंधान तथा प्रमुख सचिव कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं निर्यात प्रोत्साहन की जिम्मेदारी दी गई है। कृषि विभाग से हटाकर रविंद्र को अब प्रमुख सचिव पंचायती राज बनाया गया है। अमित गुप्ता प्रमुख सचिव स्टॉप एवं रजिस्ट्रेशन को प्राविधिक शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद, उपभोक्ता मामले तथा आयुक्त खाद्य एवं रसद रणवीर प्रसाद को प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा के साथ यूपी पावर कॉरपोरेशन, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन, राज्य विद्युत उत्पादन निगम और यूपीएसएलडीसी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि इस पद लम्बे समय से रहे और उर्जा मंत्री एके शर्मा से विवाद के कारण अब डॉ. आशीष कुमार गोयल, अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवायोजन होंगे।

## लोकभवन में सीएम योगी ने पुलिस में चयनित

## ६१२ अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगले छह माह में प्रदेश के एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य है। इसके लिए हर सप्ताह एक बड़ा भर्ती इवेंट होगा। उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जो कर नहीं पाए, वे हमेशा बोलेंगे। जिन लोगों ने अपनी अकर्मण्यता और अक्षमता से उत्तर प्रदेश को बीमार राज्य बनाया, उनके निकम्मेपन और निठल्लेपन को प्रदेश और देश देख चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष गिनता जाए, सरकार नियुक्तियां देती जाएगी। मुख्यमंत्री योगी रविवार को लोक भवन में यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की लिपिक संवर्ग सीधी भर्ती-२०२३ के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय, सहायक उपनिरीक्षक लिपिक और सहायक उपनिरीक्षक लेखा के ६१२ चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। इनमें १७३ महिलाएं भी शामिल हैं। योगी ने कहा कि २०१७ से पहले भर्ती का

विज्ञापन आते ही युवाओं के मन में यह भरोसा नहीं होता था कि बिना सिफारिश और लेनदेन के चयन हो सकेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा और चयन प्रक्रिया पर सवाल उठते थे और पेपर लीक की घटनाएं होती थीं। यहां तक कि कुछ मामलों में परीक्षा कोई और देता था और नियुक्ति किसी दूसरे की होती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब विज्ञापन से लेकर परीक्षा, नियुक्ति, प्रशिक्षण और तैनाती तक किसी अभ्यर्थी को सिफारिश की जरूरत नहीं होगी। योगी ने दावा किया कि २०१७ के बाद साढ़े नौ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा में अवसर मिला है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना जारी रखते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की पहचान भी बदली है। उनके अनुसार पहले दंगे, कर्फ्यू और माफिया की चर्चा होती थी, जबकि अब कुंभ, महाकुंभ और दूसरे बड़े आयोजन शांतिपूर्वक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस बल को मजबूत करने के साथ प्रशिक्षण क्षमता छह हजार से बढ़ाकर ६० हजार से अधिक की

गई है। महिला पुलिसकर्मियों की संख्या ४४ हजार से अधिक पहुंचने का भी दावा किया। योगी ने कहा कि पुलिस में खाली पद भरने के साथ तकनीकी क्षमता बढ़ाने पर भी काम हुआ है। हर जिले में साइबर थाना और थानों में साइबर हेल्प डेस्क, रेंज स्तर पर फॉरेंसिक लैब तथा सात शहरों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस को बदलती तकनीक के अनुरूप लगातार तैयार करना होगा। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि पुलिस सेवा में कर्तव्य पहले और अधिकार बाद में आते हैं। नौकरी मिलने के बाद अहंकार नहीं आना चाहिए। वहीं डीजीपी राजीवेंष्ण ने बताया कि करीब ३५ हजार पदों पर सीधी भर्ती और ६,४५७ पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है। नवचयनित अभ्यर्थियों का आधारभूत प्रशिक्षण छह अक्तूबर से शुरू होगा। छह माह के संस्थागत और तीन माह के व्यावहारिक प्रशिक्षण के बाद उन्हें तैनाती दी जाएगी।

## छह लोगों का सिस्टम पर कब्जा

इंदौर। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में 'छात्रों की गुंज' कार्यक्रम में नेता, उद्योगपति और अधिकारी के नेक्सस को सिस्टम बताते हुए कहा कि भारत के सिस्टम पर छह लोगों का कब्जा है। उन्होंने मंच पर बड़ी स्क्रीन के ऊपर छह लोगों की तस्वीर दिखाई और दावा किया कि ये छह लोग देश का सिस्टम चला रहे हैं। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल और दो कारोबारी गौतम अडानी व मुकेश अंबानी की तस्वीर थी। कार्यक्रम के दौरान तीन छात्रों ने राहुल से सिस्टम की बात की। इसका हवाला देते हुए राहुल ने स्क्रीन पर स्लाइड दिखाई और कहा, तीन फ्रेंड्स ने सिस्टम की बात की। सिस्टम क्या है, सिस्टम में कई लेयर हैं, टॉप लेवल पर छह लोग बैठे हैं। इसे मोदी चलाते हैं। उन्होंने सबके बारे में बताते हुए कहा, 'धमकाने का काम, उन्हें मारने

का काम, पैलेट गन मारने का काम शाह करते हैं। अजित डोवाल कहते हैं कि देश को कंट्रोल करना है तो पांच सौ लोगों को कंट्रोल करने की जरूरत है। ये देश के कम्युनिकेशन पर कब्जा किए हैं। ये फोन टैपिंग कराते हैं, ये मोदी व शाह को सूचना देते हैं। आपके फोन के अंदर डोवाल बैठे हैं। बाकी तीन लोगों के बारे में राहुल ने कहा, 'बीच में भागवत जी हैं जो विचारधारा की बात करते हैं, जिनके संगठन को हजारों करोड़ मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ अंबानी और अडानी हैं। ये लोग फाइनेंस करते हैं। पैसा घुमाकर भाजपा को दिया जाता है। उन्होंने आगे कहा, 'इस लेयर के नीचे हर संस्था को कैप्चर करके रखा है। इसमें मीडिया, एंटरटेनमेंट, न्याय सभी में एक एक आदमी बिठा रखा है। जैसे देश में कई क्रिकेटर्स हैं लेकिन सिस्टम ने शाह के बेटे को क्रिकेट का ठेका दे दिया है। यहां डेमोक्रेसी की बात होती है लेकिन सिस्टम अपने आदमी को बिठा देता है'।



# सम्पादकीय

## यूपीआई पर शुल्क का शिकंजा, डिजिटल आत्मनिर्भरता पर सवाल

तकनीक की दुनिया में भारत की जिन उपलब्धियों की चर्चा वैश्विक स्तर पर होती है, उनमें यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) प्रमुख है। यूपीआई ने न केवल डिजिटल भुगतान को आसान बनाया, बल्कि देश में वित्तीय लेनदेन की पूरी तस्वीर बदल दी। छोटे दुकानदार से लेकर बड़े कारोबारी तक, आज करोड़ों लोग इसके जरिए सहजता से भुगतान स्वीकार और करते हैं। लोगों की जिंदगी आसान बनाने की कसौटी पर भारत की यह वित्तीय तकनीक पूरी तरह खरी उतरी है। ऐसे में यूपीआई के इस्तेमाल को महंगा बनाने वाली कोई भी व्यवस्था स्वाभाविक रूप से चिंता पैदा करती है। २००० रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर मर्वेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) अथवा भुगतान शुल्क तय करने का फैसला इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। फिलहाल ऐसे भुगतानों पर ०.४ प्रतिशत शुल्क की व्यवस्था की गई है। सरकार का तर्क



हो सकता है कि इस शुल्क का भुगतान खरीदार नहीं, बल्कि व्यापारी करेगा, लेकिन व्यवहार में इसका पूरा बोझ केवल विक्रेता तक सीमित रहेगा, यह मानना कठिन है। क्रेडिट कार्ड के पुराने अनुभव बताते हैं कि भुगतान संबंधी शुल्क का कुछ हिस्सा अंततः उपभोक्ता तक पहुंच सकता है। यदि ऐसा होता है तो यूपीआई की सबसे बड़ी ताकत—कम लागत और सहजता—प्रभावित होगी। यूपीआई की सफलता का एक बड़ा कारण यह रहा है कि इसे आम लोगों के लिए सरल और कम खर्च वाला भुगतान माध्यम बनाया गया। छोटे दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे कारोबारियों के लिए डिजिटल भुगतान की सुविधा तभी उपयोगी है, जब उन्हें इसके लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ न उठाना पड़े। यदि शुल्क लगातार बढ़ते हैं तो व्यापारी नकद लेनदेन या दूसरे भुगतान माध्यमों की ओर लौटने पर विचार कर सकते हैं। इसका असर डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार पर भी पड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू अंतरराष्ट्रीय व्यापार दबाव से जुड़ा है। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) की रिपोर्टों में भारत की जीरो-एमडीआर नीति और घरेलू भुगतान नेटवर्क रुपये को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था पर आपत्तियां दर्ज की गई हैं। अमेरिका लंबे समय से विभिन्न देशों में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में अपनी कंपनियों के लिए अधिक अवसर की मांग करता रहा है। ब्राजील के पिक्स तथा इंडोनेशिया और वियतनाम के घरेलू भुगतान नेटवर्कों को लेकर भी ऐसी चर्चाएं सामने आई हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि भारत की डिजिटल भुगतान नीति का निर्धारण मुख्य रूप से देश की अपनी जरूरतों के आधार पर हो रहा है या उस पर बाहरी व्यापारिक दबाव का भी प्रभाव है। यूपीआई के इस्तेमाल में विदेशी कंपनियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। फोनपे, गूगलपे और अमेजन जैसे ऐप इसके बड़े माध्यम हैं। इसलिए यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लागू होने से भुगतान के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में धन के वितरण का स्वरूप भी बदलेगा। दूसरी ओर, भारत के घरेलू भुगतान नेटवर्क रुपये ने जिस तरह विदेशी कार्ड नेटवर्कों के सामने एक विकल्प तैयार किया है, वह डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रहा है। यहां मूल प्रश्न किसी कंपनी या देश के पक्ष अथवा विरोध का नहीं, बल्कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक दिशा का है। यूपीआई को विश्वस्तरीय सफलता बनाने में सरकार, बैंकों, तकनीकी संस्थानों, कारोबारियों और उपभोक्ताओं सभी की भूमिका रही है। इसलिए इसकी लागत और शुल्क से जुड़े फैसलों में भी व्यापक राष्ट्रीय हित, छोटे कारोबारियों की क्षमता और उपभोक्ताओं की सुविधा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। भारत ने दुनिया को दिखाया है कि कम लागत, सरलता और व्यापक पहुंच के आधार पर डिजिटल भुगतान का एक प्रभावी मॉडल बनाया जा सकता है। अब चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि राजस्व और व्यापारिक हितों के बीच संतुलन बनाते हुए यूपीआई की मूल भावना कमजोर न पड़े। डिजिटल भारत की सफलता तभी टिकाऊ होगी, जब उसकी सुविधाएं आम नागरिक और छोटे कारोबारी की पहुंच में बनी रहें।

## योगी ने कहा कि बड़े चुनाव के नतीजे किसी एक कारण से नहीं

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में २०२७ के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी गणित, सामाजिक न्याय, रोजगार, निवेश, एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, पेपर लीक, आवारा पशुओं, खाद की उपलब्धता और धार्मिक पर्यटन समेत कई मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा। योगी ने कहा कि बड़े चुनाव के नतीजे किसी एक कारण से नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व, उम्मीदों, स्थानीय मुद्दों, शासन, उम्मीदवार और रोजमर्रा की जिंदगी में सरकार के अनुभव समेत कई कारकों से तय होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की कोशिश चुनावी समीकरण साधने के बजाय प्रदेश के हर वर्ग को विकास की यात्रा में शामिल करने की रही है। उन्होंने कहा, "लाभार्थी की कोई जाति नहीं होती। लाभार्थी एक ऐसी श्रेणी है जो जाति से ऊपर है और यही हमारा गणित और हमारा राजनीतिक फार्मूला है।" विपक्ष की पीडीए रणनीति और सहयोगी दलों की राजनीति से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव कई चीजों से तय होते हैं। इनमें प्रतिनिधित्व, लोगों की उम्मीदें, स्थानीय मुद्दे, गवर्नंस, उम्मीदवार और सरकार के साथ लोगों का रोजमर्रा का अनुभव शामिल है। योगी ने दावा किया कि २०१७ और २०२२ में ओबीसी और दलित समुदायों के बड़े हिस्से ने सरकार का समर्थन किया, क्योंकि सरकार ने बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ पहुंचाया। उन्होंने गरीबों को राशन, पक्का घर, पानी, शौचालय और बिजली जैसी सुविधाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय का अर्थ केवल प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि नौकरी, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, सुरक्षा और अवसरों तक समान पहुंच भी है। गठबंधन और सीटों के बंटवारे से जुड़े सवाल पर योगी ने कहा कि ये संगठन के स्तर पर बातचीत के विषय हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि शासन हर समुदाय, हर जिले और हर घर तक पहुंचे। रोजगार और निवेश के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निवेश को आर्थिक गतिविधियों, उद्यम और नौकरियों में बदलने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने २०२३ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को ३३.५ लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले थे, जिनसे ६३ लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा होने की संभावना जताई गई थी। योगी के मुताबिक, इन प्रस्तावों का बड़ा हिस्सा एमओयू चरण से आगे बढ़ चुका है और करीब ७.५ लाख करोड़ रुपये का निवेश ग्राउंड-ब्रेकिंग के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मानव संसाधन को मानव पूंजी में बदलने पर जोर दे रही है। इसके लिए उद्योग आधारित कौशल विकास, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर

(GCC), इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ६६ लाख से अधिक एमएसएमई, २४ हजार से ज्यादा स्टार्टअप और ३५ हजार से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। इसके साथ ही औद्योगिक गलियारों के आसपास २७ समन्वित विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स संकुल विकसित किए जा रहे हैं। योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश का युवा केवल सरकारी नौकरी नहीं चाहता। वह प्रदेश में पढ़ाई, काम, कारोबार और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर चाहता है। सरकार का उद्देश्य केवल



पलायन रोकना नहीं, बल्कि युवाओं को उत्तर प्रदेश में ही अपना भविष्य बनाने का विकल्प देना है। उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश तेजी से आर्थिक विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि राज्य का जीएसडीपी २०१६-१७ में १३.३० लाख करोड़ रुपये से बढ़कर २०२५-२६ में करीब ३६ लाख करोड़ रुपये हो गया है और चालू वित्त वर्ष में इसके करीब ४० लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण में भी २०२५-२६ के लिए जीएसडीपी करीब ३६ लाख करोड़ रुपये अनुमानित की गई थी। योगी ने कहा कि अगले चरण में औद्योगिकीकरण, निर्यात, एमएसएमई और बेहतर वैल्यू वाली नौकरियों पर जोर होगा। उन्होंने कहा कि विकास सिर्फ नोएडा और गाजियाबाद तक सीमित नहीं रह सकता। पूर्वांचल और बुंदेलखंड को विकास के अगले चरण का अहम इंजन बनाना होगा। मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का उल्लेख किया। वहीं पूर्वांचल के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक क्लस्टरों को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि गोरखपुर उद्योग और माल परिवहन का बड़ा केंद्र बन सकता है। वाराणसी में टेक्सटाइल, हस्तशिल्प, पर्यटन और सेवा क्षेत्र में संभावनाएं हैं, जबकि बुंदेलखंड विनिर्माण और रक्षा क्षेत्र से जुड़े उद्योगों का केंद्र बन सकता है। आवारा पशुओं की समस्या पर योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है और ग्रामीण जीवन से जुड़ी कुछ पुरानी चुनौतियों को खत्म करने में समय लगता है। सरकार ने पशु आश्रय स्थलों और उनके प्रबंधन की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि परिणाम दिखाई दे रहे हैं,

लेकिन जब तक किसान पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं करता, तब तक सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी। प्रदेश में खाद की किल्लत को लेकर उठ रहे सवालों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि किसान को जरूरत के समय खाद उपलब्ध हो। साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में पिछले वर्षों में सुधार हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े कृषि प्रधान राज्य में यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण से जुड़े सवाल पर योगी ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में संवैधानिक आरक्षण लागू किया गया है। उन्होंने दावा किया कि पिछले नौ वर्षों में प्रदेश में करीब ६.५० लाख नियुक्तियों की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी परीक्षा में गड़बड़ी हुई तो उसे रद्द कर दोबारा परीक्षा कराई गई, भले ही इससे प्रशासनिक खर्च बढ़ा हो। उनका कहना था कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से उन युवाओं को फायदा होता है, जिनके पास प्रभाव या आर्थिक संसाधन नहीं हैं। हाल में हुई कांस्टेबल और होमगार्ड भर्ती का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ७५ हजार से अधिक पदों के लिए युवाओं की भागीदारी यह दिखाती है कि उन्हें चयन प्रक्रिया पर भरोसा है। पेपर लीक और विरोध प्रदर्शनों से जुड़े सवाल पर योगी ने कहा कि शांतिपूर्ण असहमति, सरकार की आलोचना और वैध विरोध लोकतांत्रिक अधिकार हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी असहमति रोकना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि विरोध हिंसा, धमकी, परीक्षा में धोखाधड़ी या सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान में न बदले। पेपर लीक के संदर्भ में उन्होंने कहा कि कार्रवाई परीक्षा प्रश्नपत्र लीक और उसे बेचने वालों के खिलाफ है, छात्रों के खिलाफ नहीं। उनके मुताबिक, परीक्षा दोबारा कराने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मेहनत करने वाले छात्र को अनुचित तरीके से परीक्षा पास करने वाले व्यक्ति से नुकसान न हो। धार्मिक पर्यटन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या, काशी और मथुरा-वृंदावन उत्तर प्रदेश की सभ्यतागत विरासत का हिस्सा हैं। उनके मुताबिक, विरासत संरक्षण और आर्थिक विकास साथ-साथ चल सकते हैं। योगी ने काशी विश्वनाथ धाम का उदाहरण देते हुए कहा कि २०२१ में इसके उद्घाटन के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और इससे स्थानीय स्तर पर नाविकों, बुनकरों, दुकानदारों, पुजारियों, ऑटो चालकों, होटल कारोबारियों और होमस्टे संचालकों को आर्थिक गतिविधियों का लाभ मिला है। उन्होंने अयोध्या और प्रयागराज में भी पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विस्तार का उल्लेख किया।

# नियुक्ति पत्र मिलते ही खिल उठे अभ्यर्थियों के चेहरे

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नियुक्ति पत्र पाकर लिपिक संवर्ग सीधी भर्ती-२०२३ के चयनित अभ्यर्थियों के चेहरे खिल उठे। चयनित अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और



पारदर्शी बताते हुए कहा कि लिखित परीक्षा से लेकर टाइपिंग और मेडिकल तक पूरी प्रक्रिया में उन्हें किसी तरह की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी। उनके मुताबिक मेहनत और योग्यता के आधार पर चयन होने से वर्षों से देखा जा रहा सरकारी नौकरी का सपना पूरा हुआ है। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में यूपी पुलिस के ६१२ चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इनमें पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) और पुलिस सहायक उपनिरीक्षक

(लेखा) के पदों पर चयनित अभ्यर्थी शामिल हैं। लखनऊ निवासी संजीव वर्मा का चयन उपनिरीक्षक (गोपनीय) के पद पर हुआ है। उन्होंने बताया कि परीक्षा दो नवंबर २०२५ को हुई थी और मार्च

२०२६ में परिणाम आया। संजीव के मुताबिक पूरी नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष रही और मेहनत करने वालों को सफलता मिली। मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र पाना उनके लिए गर्व का क्षण है। लखीमपुर खीरी निवासी रजत गुप्ता भी उपनिरीक्षक (गोपनीय) के पद पर चयनित हुए हैं। यह यूपी पुलिस में उनका दूसरा चयन है। वर्ष २०२० में वह आरक्षी पद पर चयनित हुए थे। उन्होंने कहा कि लिखित परीक्षा, टाइपिंग और मेडिकल तक प्रक्रिया पारदर्शी रही। सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) पद

पर चयनित अंजू भारती ने कहा कि उनका चयन बिना पक्षपात, लेनदेन और सिफारिश के हुआ। उनके अनुसार उन्होंने नौकरी के लिए केवल आवेदन फॉर्म भरने में पैसा खर्च किया। इसी पद पर चयनित आदर्श कुमार जैन ने भी भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष बताते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया। सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) पद पर चयनित दर्शना बाजपेयी ने बताया कि भर्ती में कहीं सिफारिश या लेनदेन की जरूरत नहीं पड़ी और योग्यता के आधार पर चयन हुआ। तीन वर्ष की तैयारी के बाद मिली सफलता को उन्होंने अपने और परिवार के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र मिलना उनके लिए यादगार क्षण है। सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के पद पर चयनित धीरेंद्र सिंह ने बताया कि वह पांच वर्ष से तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों को सफलता मिली और नियुक्ति पत्र मिलने का दिन उनके लिए बेहद खुशी का है। सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) पद पर चयनित सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने बताया कि वह २०२१ से तैयारी कर रहे थे। उनके मुताबिक पूरी भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रही।

# मेडिकल कॉलेजों में एससी आरक्षण पर मायावती ने सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश के चार मेडिकल कलेजों में अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के लिए अतिरिक्त आरक्षण पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने के मामले में योगी सरकार से उच्चतम न्यायालय में अपील करने की मांग की है। सुश्री मायावती ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा, "सामाजिक न्याय की जरूरत और मांग यही है कि यूपी सरकार माननीय न्यायालय में इस बात की पुरजोर पैरवी करती कि एससी समाज के हित व कल्याण हेतु 'स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान' के धन से जिला सहारनपुर, अम्बेडकरनगर, कन्नौज और जालौन में बनाये गये मेडिकल कालेजों में एससी वर्ग हेतु अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था ५० प्रतिशत के सामान्य आरक्षण से अलग है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की भरपूर उपयोगिता साबित होती है, तो शायद माननीय अदालत इस पर

जरूर सकारात्मक विचार करता और इस पर रोक नहीं लगाता। बसपा सुप्रीमो ने अपने दूसरे बिंदु में कहा कि किन्तु अब जबकि उच्च न्यायालय ने इस पर पाबंदी लगा दी है और मेडिकल दाखिला भी अब इससे प्रभावित है, तो ऐसे में यूपी सरकार तुरंत उच्चतम न्यायालय में अपेक्षित राहत के लिए अपील करे तो यह उचित होगा। उल्लेखनीय है कि बसपा



सरकार के कार्यकाल में एससीपी फंड से इन चार जिलों में मेडिकल कलेजों की स्थापना की गई थी, जिनमें एससी छात्रों के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान किया गया था। हाईकोर्ट के हालिया फैसले के बाद इन कलेजों में प्रवेश प्रक्रिया पर असमंजस की स्थिति बन गई है।

# अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा- सत्ता में आए तो 'कार कैसे पलटी' की कराएंगे जांच, रिमोट सेंसिंग से तलाशेंगे रास्ता

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे से जुड़ी कथित मुठभेड़ की तरफ इशारा करते हुए तंज किया कि उनकी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आती है तो वह 'रिमोट सेंसिंग' विभाग (दूर संवेदी विभाग) से 'कार पलटने' वाली घटना की जांच कराएंगे। कानपुर देहात के बिक: इलाके में दो-तीन जुलाई २०२० की रात को आठ पुलिसकर्मियों की घात लगाकर छत से गोलियां चलाते हुए हत्या किये जाने की वारदात के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे की १० जुलाई को उज्जैन से कानपुर लाते समय पुलिस की गाड़ी कथित रूप से दुर्घटनाग्रस्त होकर श्पलटर् गयी थी और पुलिस का दावा है कि हादसे के बाद भागने की कोशिश में दुबे पुलिस से हुई मुठभेड़ में मारा गया था। सपा प्रमुख ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि रिमोट सेंसिंग के साथ-साथ सभी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल मुख्य रूप से किसानों के फायदे के लिए और साथ ही स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रूि के क्षेत्रों में किया जाएगा। अखिलेश यादव ने किसी का नाम लिये बगैर गैंगस्टर विकास दुबे की कथित मुठभेड़ में हुई मौत की ओर इशारा करते हुए कहा, शरिमोट सेंसिंग विभाग एक बहुत पुराना विभाग

है। हम निश्चित रूप से इस विभाग को उस घटना की जांच का काम सौंपेंगे कि आखिर गाड़ी कैसे पलटी थी। १३ उन्होंने कहा, शहम उन्हें अलग से फंड देंगे... चाहे वह ५० करोड़ रुपये हो या १०० करोड़ रुपये... और उन्हें उन गाड़ियों की आवाजाही का पता लगाने का निर्देश देंगे कि वे कहां से चली थी



और उस जगह तक कैसे पहुंची? इसके अलावा, हम अपराध से निपटने के लिए रिमोट सेंसिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करेंगे, जिससे फर्जी एनकाउंटर जैसी घटनाओं पर भी रोशनी डालने में मदद मिलेगी।" सपा प्रमुख ने गैंगस्टर विकास दुबे के मुठभेड़ में मारे जाने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि कार पलटी नहीं थी, बल्कि यह सरकार को गिरने से बचाने की कोशिश थी ताकि 'सच' सामने न आए। पुलिस ने दावा किया था कि उज्जैन से कानपुर ले जाई जा रही पुलिस की गाड़ी के १० जुलाई को दुर्घटनाग्रस्त होने और विकास दुबे के मौके से भागने की कोशिश करने के बाद हुई मुठभेड़ में वह मारा गया था।

# कानपुर में ५,००० EVM और १२ इंजीनियर पहुंचे? जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया पूरा सच

लखनऊ/कानपुर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव २०२७ से पहले कानपुर नगर में ५,००० इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और १२ इंजीनियरों के पहुंचने का सोशल मीडिया पर किया जा रहा दावा भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत है। कानपुर नगर के जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल के माध्यम से इस दावे का खंडन किया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानपुर नगर में ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच (First Level Checking & FLC) निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रही है और इस प्रक्रिया के लिए किसी अन्य स्थान से नई ईवीएम नहीं लाई गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, कानपुर नगर में ईवीएम की प्रथम

स्तरीय जांच १७ सितंबर २०२६ से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में शुरू हो चुकी है। यह प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के तहत जारी है। प्रशासन ने बताया कि एफएलसी के



आयोजन से जुड़ा पूरा शेड्यूल और अन्य आवश्यक जानकारी पहले ही सार्वजनिक की जा चुकी है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि कानपुर नगर में ५,००० ईवीएम और १२ इंजीनियर पहुंचाए गए हैं। जिला निर्वाचन

अधिकारी ने इसे पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है। प्रशासन के मुताबिक, एफएलसी के लिए कानपुर नगर में किसी दूसरे स्थान से कोई नई ईवीएम नहीं लाई गई है। इसलिए सोशल मीडिया पर प्रसारित दावे को लेकर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली अपुष्ट और भ्रामक सूचनाओं पर विश्वास न करें। चुनाव से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने को कहा गया है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि भ्रामक सूचनाएं या अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

# नाक काटने वाले पति और गुप्तांग काटने वाली पत्नी पर केस दर्ज!

हरदोई। साण्डी कस्बे में पति-पत्नी के बीच विवाद का मामला पुलिस तक पहुंच गया है। पहले पत्नी की नाक काटने के आरोप में पति और सास-ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसके कुछ घंटे बाद पुलिस ने पति की ओर से लगाए गए आरोप के आधार पर पत्नी के खिलाफ भी जबरन घर में घुसकर मारपीट करने और पति के गुप्तांग को दांत से काटने का मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी है। साण्डी कस्बे के मोहल्ला मुंशीगंज निवासी दीपक की पत्नी साधना पहले अपने मायके चली गई थी। इसके बाद वह वहीं से अपने चचेरे देवर के साथ कहीं चली गई थी। गुरुवार को साधना कथित तौर पर ससुराल पहुंची। इस दौरान उसकी ससुराल वालों से कहासुनी हुई। अगले दिन भोर में विवाद बढ़ गया। आरोप लगाया गया कि पति दीपक ने साध

ना की नाक काट दी। इस मामले में पति दीपक के अलावा उसकी मां और पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। दूसरी ओर, दीपक ने आरोप लगाया कि पत्नी साधना ने उसके साथ मारपीट की और अपने दांत से उसका गुप्तांग काट लिया। मामले में उसी दिन शाम को दीपक की मां शशि देवी की तहरीर पर साण्डी पुलिस ने साधना के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

# हामिद अंसारी के बयान पर विवाद

नई दिल्ली। पूर्व उप राष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी जब भी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो उनके बयान पर विवाद होता है। संविधान के जानकार, वरिष्ठ वकील और लेखक दिवंगत एजी नूरानी की याद में आयोजित एक कार्यक्रम में शनिवार को हामिद अंसारी ने ऐसा बयान दिया, जिसे लेकर भाजपा ने उनके ऊपर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ओगी आदित्यनाथ ने भी उनको निशाना बनाया है। हामिद अंसारी ने अपने बयान में कहा कि देश के हिंदू सांप्रदायिकता ज्यादा खतरनाक है। असल में हामिद अंसारी ने एजी नूरानी की किताब 'द आरएसएस: ऑमेनेस टू इंडिया' का जिक्र करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री

जवाहरलाल नेहरू के एक बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के लिए असली खतरा कम्युनिज्म नहीं, बल्कि हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता है। नई



दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए हामिद अंसारी ने कहा कि नूरानी की २०१६ में प्रकाशित किताब की प्रस्तावना में ऐसे विचार दर्ज हैं,

जो उनके मुताबिक आज भारत के कई मुसलमानों की भावना को दिखाते हैं। अंसारी ने आगे कहा कि इसी किताब की प्रस्तावना में नूरानी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उन टिप्पणियों का जिक्र किया था, जिन्हें पूर्व विदेश सचिव जगत सिंह गुंडेविया ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की एक बैठक के संदर्भ में दर्ज किया था। अंसारी के अनुसार, नेहरू ने उस बैठक में कहा था कि भारत के लिए वास्तविक खतरा कम्युनिज्म नहीं, बल्कि हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता है। गौरतलब है कि केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार के समय भी हिंदू सांप्रदायिकता को लेकर बहुत विवाद हुआ था।

# गूगल जेमिनी एआई ने सुरक्षा परीक्षण के दौरान तीन कंपनियों के सिस्टम में लगाई सेंध

गूगल के कृत्रिम मेधा (एआई) मॉडल जेमिनी ने साइबर सुरक्षा क्षमताओं के परीक्षण के दौरान तीन कंपनियों के सिस्टम में स्वायत्त रूप से सेंध लगाई। कंपनी ने यह जानकारी दी है। इसे इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देने वाला जेमिनी का पहला ज्ञात मामला माना जा रहा है। यह घटना इजरायली साइबर सुरक्षा फर्म 'इर्रेगुलर' के एक ऑनलाइन परीक्षण के दौरान हुई। परीक्षण के तहत एआई मॉडल को एक काल्पनिक वातावरण में एक नकली कंपनी के डेटा पर लक्ष्य साधने का काम दिया गया था। परीक्षण प्रणाली के इंटरनेट से जुड़े होने और नकली कंपनी का नाम एक वास्तविक कंपनी से मेल खाने के कारण जेमिनी ने इंटरनेट पर मौजूद सार्वजनिक जानकारी का उपयोग किया तथा पासवर्ड एवं क्रेडेंशियल्स का अनुमान लगाकर

असली कंपनियों के सर्वर तक पहुंच बना ली। बीबीसी ने गूगल अधिकारी के हवाले से बताया कि जैसे ही मॉडल को इसका अहसास हुआ, 'मॉडल स्वतः ही रुक गया'। गूगल की सुरक्षा इंजीनियरिंग



उपाध्यक्ष हीदर एडकिन्स ने एक बयान में कहा, "हमने तीनों प्रभावित कंपनियों को इसकी जानकारी दे दी है और अपने ट्रेनिंग पार्टनर के साथ मिलकर परीक्षण प्रक्रियाओं में आवश्यक सुधार किये हैं।" उन्होंने कहा कि यह घटना शक्तिशाली एआई मॉडलों को जिम्मेदारी से कार्य करने के लिए

प्रशिक्षित करने का महत्व बताती है। गौरतलब है कि हाल ही में अन्य एआई सिस्टमों में भी इस तरह के उल्लंघन देखे गये हैं। इससे पहले जुलाई में एंथ्रोपिक के क्लॉड और ओपनएआई के मॉडलों के भी सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने और साइबर हमलों को अंजाम देने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। एआई के विकास की गति और इससे पैदा होने वाले संभावित खतरों को लेकर तकनीकी जगत और वैश्विक नेताओं के बीच अच्छी खासी बहस तेज हो गयी है। जहां एक ओर एनवीडिया के सीईओ जेन्सन हुआंग ने एआई विकास को तेज गति से आगे बढ़ाने की वकालत की है, वहीं ओपनएआई के मुख्य कार्यकारी सैम आल्टमैन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में इस तकनीक की सुरक्षा पर अपनी बात रखने वाले हैं।

# चुनाव चिन्ह के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता

नई दिल्ली। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का नाम और दो पतियां चुनाव चिन्ह फ्रीज किए जाने के खिलाफ ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। उन्होंने अपनी याचिका में चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतुब्रत बनर्जी को पक्ष बनाया है। ममता की ओर से इस मामले में जल्दी सुनवाई की अपील की गई है। गौरतलब है कि गुरुवार, १७ सितंबर को चुनाव आयोग ने टीएमसी के दोनों गुटों को मूल नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने से रोकते हुए अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह दिए थे। राज्य में दो सीटों पर हो रहे

उपचुनाव में दोनों गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह पर लड़ना है। आयोग ने ममता गुट को 'ममता अल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' नाम और 'फुटबॉल प्लेयर'



चिन्ह मिला, जबकि दूसरे गुट को 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' नाम और 'लिफाफा' चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। असल में ममता बनर्जी की पार्टी में विवाद

# देश में सबसे ज्यादा प्रश्नपत्र लीक

# उत्तर प्रदेश में हुए : अखिलेश यादव

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए रविवार को दावा किया कि देश में सबसे ज्यादा प्रश्नपत्र लीक उत्तर प्रदेश में हुए हैं। इससे पहले रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा लिपिक संवर्ग में चयनित ६१२ अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर योगी ने कहा कि २०१७ से पहले परीक्षाओं की शुचिता और चयन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठते थे तथा प्रश्नपत्र लीक के मामले अलग से सामने आते थे। योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की उपलब्धियों के साथ २०१७ के बाद परीक्षा प्रक्रिया में शुचिता और सुधार का विस्तार से उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि योग्य अभ्यर्थियों को हर हाल में अवसर मिले। सपा प्रमुख ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा, "देश में अगर प्रश्नपत्र लीक हुए हैं तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में लीक हुए हैं।" यादव ने राज्य में विकास के दावों को

खोखला बताते हुए कहा, रश्मिनेश आया ही नहीं। सपने तो दिखाए कि निवेश आएगा, उद्योग लगेगा, रोजगार बढ़ेंगे, लेकिन निवेश आया ही नहीं।" अखिलेश यादव ने कहा कि आज भी जमीनें खाली पड़ी हैं, किसानों से जमीन तो ले ली गई लेकिन प्रदेश के हर क्षेत्र में किसानों को न तो मुआवजा मिला और न



ही सर्किल रेट बढ़ाया गया। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार न तो बाबा साहेब ड. भीमराव आंबेडकर का सम्मान करती है, न उनकी मूर्तियों का और न ही उनके अनुयायियों का। अखिलेश यादव ने दावा किया, "भाजपा की सरकार में हर साल १५ से ज्यादा (आंबेडकर) मूर्तियां क्षतिग्रस्त की गई हैं।" उन्होंने दावा किया कि राज्य के ७२ जिलों में बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की १५१ मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है, जबकि इस मामले में केवल १४ गिरफ्तारियां हुई हैं।

# डीयू में एबीवीपी को मिली जीत

नई दिल्ली। जंतर मंतर पर हुए छात्रों के प्रदर्शन के बाद युवाओं व छात्रों की नाराजगी के बीच सबकी नजर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी डूसू के चुनावों पर थी। शनिवार को आए नतीजों में एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बाजी मारी है। कांटे की टक्कर में एबीवीपी ने तीन सीटों पर जीत दर्ज की। अध्यक्ष पद पर उसके यश डबास जीते। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई को एक भी सीट नहीं मिली। लेफ्ट का गठबंधन भी नाकाम रहा। अध्यक्ष पर एबीवीपी के यश डबास ने एनएसयूआई के जितेंद्र कुमार मीणा को दो हजार के करीब वोटों से हराया। उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय दीपांशु शौकीन ने रिकर्ड बनाया। १७ साल के बाद डूसू के सेंट्रल पैनल में किसी पद पर निर्दलीय की जीत हुई है। शौकीन को ३० हजार से ज्यादा वोट मिले। एनएसयूआई से टिकट नहीं मिलने के बाद वे निर्दलीय लड़े थे। सबसे बड़ी जीत उनकी है। इससे पहले २००६ में निर्दलीय मनोज चौधरी और १९६१ में निर्दलीय राजीव गोस्वामी डूसू के अध्यक्ष बने थे। एबीवीपी की रिया छावड़ी को सचिव और लक्ष्यराज सिंह को संयुक्त सचिव पद पर जीत मिली।

गौरतलब है कि डूसू चुनाव के लिए शुक्रवार को ५२ कलेजों में मतदान हुआ था। इसमें ४०.४६ फीसदी वोटिंग हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय के १,५१,५१६ छात्रों में से ६१,३१२ ने मतदान किया। चुनाव नतीजे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एबीवीपी को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया



में लिखा, 'दिल्ली विश्वविद्यालय केवल एक यूनिवर्सिटी नहीं, यहां देश के हर कोने से विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। यहां का जनादेश पूरे भारत के युवाओं के मन का प्रतिबिंब होता है। आज एबीवीपी को मिली शानदार जीत उन राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए स्पष्ट संदेश है, जो युवा शक्ति को राष्ट्रविरोधी एजेंडे की प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं। देश का युवा आज राष्ट्र प्रथम की विचारधारा के साथ मजबूती से खड़ा है और यही इस जनादेश का सबसे बड़ा संदेश है'।

## एनटीए का ऑफिस देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज

नई दिल्ली। मेडिकल में दाखिले के लिए होने वाली नीट यूजी और नीट पीजी सहित दो दर्जन से ज्यादा अखिल भारतीय परीक्षाओं का आयोजन करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए में सुधार का सुप्रीम कोर्ट ने मिशन बनाया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है एनटीए में सुधार के लिए क्या क्या किया जा रहा है इसका पूरा ब्योरा वेबसाइट पर डालना होगा। अदालत ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर नीट परीक्षा सिस्टम की जांच के लिए जज एनटीए के ऑफिस का दौरा करेंगे। वे देखेंगे कि परीक्षा को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से कराने के इंतजाम वास्तव में काम कर रहे हैं या नहीं। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अलोक अराधे की बेंच ने शुक्रवार को यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की। इसमें एनटीए को भंग करने और पेपर लीक रोकने के लिए मजबूत

निगरानी सिस्टम की मांग की गई है। इसी मामले की सुनवाई में १६ अगस्त को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि नीट परीक्षा सिस्टम फूलप्रूफ है। इसमें संध लगाना मुश्किल है। हालांकि पिछले तीन साल में दो बार पेपर लीक



हुए हैं और परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। २०२४ में कई सेंटर्स पर दोबारा परीक्षा हुई और २०२६ पूरी परीक्षा ही रद्द हुई। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को अपने सुधारों और अब तक हुई प्रगति का ब्योरा वेबसाइट पर डालने का निर्देश दिया है। इससे परीक्षा व्यवस्था में हो रहे बदलावों की जानकारी सार्वजनिक होगी। सुनवाई के दौरान एनटीए के लिए पर्याप्त स्थायी कर्मचारी और विशेषज्ञ

स्टाफ रखने की जरूरत पर चर्चा हुई। कोर्ट ने बेहतर मैनपावर, प्रशिक्षण, इंफ्रास्ट्रक्चर और संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत बताई। एनटीए को मजबूत कानूनी आधार देने के लिए वैधानिक व्यवस्था पर भी विचार किया गया। कोर्ट ने कहा कि लिखित परीक्षा से डिजिटल परीक्षा की ओर बदलाव अचानक नहीं किया जा सकता। इसे धीरे धीरे लागू करना होगा, ताकि नई व्यवस्था में परेशानी न हो। सुनवाई के दौरान केंद्र ने कोर्ट को बताया कि नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता वाली उच्च अधिकारी प्राप्त पैनल की पहली अंतरिम रिपोर्ट सितंबर के अंत तक आने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया कि नीट परीक्षा के लिए एनटीए को यूपीएससी जैसा मजबूत सिस्टम बनाना चाहिए, जिसमें परीक्षा कराने का अनुभव अधिकारियों के ट्रांसफर होने के बाद भी संस्था के पास बना रहे।

## सिस्टम बनाम स्टूडेंट्स: राहुल

नई दिल्ली/इंदौर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की इंदौर में आखिरकार सभा हुई। बड़ी जद्दोजहद और बहुत सारी पाबंदियों के साथ राहुल को इंदौर में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम करने की अनुमति मिली। शनिवार की शाम को उन्होंने बड़ी संख्या में मौजूद युवाओं और छात्रों को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि उनके कार्यक्रम की थीम है, 'सिस्टम बनाम स्टूडेंट्स'! राहुल ने अपने भाषण में कहा कि सिस्टम पर छात्रों को भरोसा नहीं है और सिस्टम भी छात्रों की बजाय अंधा भक्तों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। राहुल ने अपने भाषण में असली छात्र और अंधभक्त के बीच का अंतर भी समझाया। इंदौर के आईडीए मैदान पर राहुल के कार्यक्रम में करीब २५ हजार युवा पहुंचे थे। कांग्रेस का दावा है कि दो लाख से ज्यादा युवाओं और छात्रों ने इसके लिए पंजीकरण कराया था। कांग्रेस ने ३५ साल से कम उम्र के युवाओं को ही इस कार्यक्रम में प्रवेश दिया

था। उनके साथ सवाल-जवाब के दौरान राहुल ने कहा, 'सिस्टम नहीं चाहता कि स्टूडेंट्स सवाल पूछें, इसलिए वह अंधभक्त पैदा करता है'। उन्होंने कहा, 'छात्रों का सिस्टम से भरोसा उठ गया है, हालांकि



कुछ जगह कैंडिडेट्स की भी गलती है'। इस पर सामने बैठे छात्रों ने जवाब दिया, 'सर, हम सिस्टम से हार गए'। राहुल इससे पहले राजस्थान से लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सहित चार जगह 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम कर चुके हैं। इंदौर में उनका पांचवां कार्यक्रम था। इसमें उन्होंने सरकार को सिस्टम बताते हुए उस पर हमला किया। उन्होंने कहा, 'सिस्टम को चलाने वालों के बच्चों को देखिए वे

इंदौर में पढ़ रहे हैं या विदेश में? ये देश के युवाओं को अंधभक्त बनाना चाहते हैं। अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे पढ़ने के लिए'। राहुल ने कहा, 'हमने शुरुआत में कहा कि स्टूडेंट देश को बनाता है, शिक्षा देश की नींव है, यह हर स्टूडेंट का हक है। स्कूल मिडडे मील से लेकर कलेज और कलेज से रोजगार तक पहुंचाना, ये सरकार का काम है'। राहुल गांधी ने आगे कहा, 'अब इंटरनेटिंग बात बताता हूं। सिस्टम को स्टूडेंट से खतरा है। क्यों खतरा है, क्योंकि स्टूडेंट सवाल पूछता है'। उन्होंने कहा, 'स्टूडेंट सवाल करता है कि अमित शाह जी के बेटे क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन कैसे बन गए? स्टूडेंट पूछता है कि हिंदुस्तान के पूरे बिजनेस को दो लोगों ने कैसे कैप्चर कर लिया? स्टूडेंट यह भी पूछता है कि ज्यूडिशियरी और बाकी संस्थाएं अपना काम क्यों नहीं करतीं और इलेक्शन कमीशन अपना काम क्यों नहीं करता'?

## निठारी कांड के आरोपी कोली का शव मिला

हरिद्वार। दिल्ली और एनसीआर सहित पूरे देश को दहला देने वाले निठारी कांड के आरोपी रहे सुरेंद्र कोली का शव शुक्रवार को हरिद्वार के भूपतवाला में उसकी चाय की दुकान में फांसी पर लटका मिला। बताया गया है कि वह पिछले कुछ महीनों से नाम बदलकर हरिद्वार में रह रहा था। शुरुआती जानकारी के आधार पर बताया जा रहा है कि आत्महत्या की है, हालांकि पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है। करीब १६ साल जेल में रहने के बाद नवंबर २०२५ में सुप्रीम कोर्ट से आखिरी

मामले में बरी होकर वह जेल से बाहर आया था। गौरतलब है कि दिल्ली से सटे नोएडा के निठारी में २००५-०६ में बच्चों और



महिलाओं के गायब होने की एक के बाद एक हुई कई घटनाओं के बाद उसका नाम सामने आया था। २६ दिसंबर २००६ को मोनिर सिंह

पंढेर की कोठी के पीछे नाले से मानव अवशेष मिलने के बाद पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। पंढेर की कोठी में ही कोली काम करता था। इस घटना का खुलासा होने के बाद सीबीआई ने मामले की जांच की और कोली के खिलाफ कई केस चले। कोली को निठारी से जुड़े १३ मामलों में मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि २०२३ में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने १२ मामलों में उसे बरी कर दिया। इसके बाद नवंबर २०२५ में सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी मामले में भी उसकी दोषसिद्धि रद्द कर दी थी।

## एफसीआरए पर बनी जेपीसी की पहली बैठक

नई दिल्ली। विदेशी चंदे के नियमन से जुड़े एफसीआरए कानून में संशोधन के लिए लाए गए बिल पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की पहली बैठक शुक्रवार को नई दिल्ली में हुई। भाजपा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति में ३१ सदस्य हैं, जिसमें भाजपा के १४ सांसद हैं। समिति में एनडीए का बहुमत है। इसलिए समिति का फैसला सरकार के बिल के खिलाफ नहीं होगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इस विवादित बिल को मार्च में पेश किया था लेकिन केरल के विधानसभा चुनाव की वजह से इसे रोक दिया था। चुनाव नतीजों के बाद संसद के मानसून सत्र में बिल को जेपीसी में भेजा गया। जेपीसी को २०२६ के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक लोकसभा में रिपोर्ट देनी है। विपक्ष का आरोप है कि एफसीआरए में संशोधन का बिल ईसाई एनजीए और अल्पसंख्यक संस्थानों की वैध फंडिंग रोक कर अल्पसंख्यकों को परेशान करने के लिए लाया गया है। सरकार ने इस आरोप खारिज करते हुए कहा

### पाकिस्तान की सफाई

नई दिल्ली। भारतीय युद्धपोत से पाकिस्तानी नौसेना का एक पोत टकराने की घटना पर पाकिस्तान की ओर से दी गई सफाई से भारत संतुष्ट नहीं है। पाकिस्तान की सफाई के बाद भी भारत ने दोहराया कि पाकिस्तान को दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का सम्मान करना चाहिए। भारत ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान



अपनी सभी सैन्य इकाइयों को सावधान रहने की सलाह दे। गौरतलब है कि पश्चिमी अरब सागर में भारतीय नौसेना के युद्धपोत को पाकिस्तानी नौसेना के एक पोत ने टक्कर मार दी थी। इस मामले में विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की सफाई को पूरी तरह खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है, 'हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। यह वही हमेशा की तरह की टालमटोल है, जिसकी हमें उम्मीद थी। हम इसमें लगाए गए आरोपों और आक्षेपों को सिरे से खारिज करते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, 'हम इस मामले के तथ्यों को फिर से दोहराना चाहेंगे कि आईएनएस कोलकाता पश्चिमी अरब सागर में

है कि बिल धर्म विशेष से जुड़ा नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि विदेशी और खास कर अमेरिका के दबाव में इस बिल को टाला जा रहा है। यह बिल इस साल २५ मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था। विपक्षी दलों के लगातार विरोध के बाद इसे १२ अगस्त को जेपीसी को भेजा गया। विपक्ष ने



आरोप लगाया था कि बिल के कुछ प्रावधान बेहद आपत्तिजनक हैं, जिसमें विदेशी फंडिंग बंद होने या एफसीआरए लाइसेंस निरस्त होने पर एनजीओ की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी शामिल है। समिति अब बिल के सभी प्रावधानों की विस्तृत जांच करेगी। लोकसभा में बिल पेश करते समय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा था कि कानून का लक्ष्य पारदर्शिता बढ़ाना है। उन्होंने कहा था कि इससे विदेश से मिले फंड का सही इस्तेमाल सुनिश्चित होगा।

### से भारत संतुष्ट नहीं

एक नियमित तैनाती पर था, तभी पाकिस्तानी नौसेना के जहाज पीएनएस हुनैन ने समुद्र में अस्वीकार्य और गैर पेशेवर तरीके से बरताव किया, जिसकी वजह से यह टक्कर हुई। बयान में आगे कहा गया, 'पीएनएस हुनैन द्वारा खतरनाक तरीके से ओवरटेक करने की पैरेबाजी अप्रैल १९६१ के 'सैन्य अभ्यासों,

पैरेबाजी और सैनिकों की आवाजाही पर पूर्व सूचना को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते के अनुच्छेद १० का घोर उल्लंघन था'। असल में भारत और पाकिस्तान ने यह समझौता किया है कि समुद्र में नौसेना इकाइयां एक दूसरे से तीन नौटिकल माइल्स यानी ५.६ किलोमीटर के दायरे में नहीं आनी चाहिए। प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तानी जहाज ने 'समुद्र में टक्कर रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय नियमों का भी उल्लंघन किया है। बहरहाल, इस घटना से आईएनएस कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और वह अभी भी समुद्र में है। इससे पहले इसी मामले में भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को बुधवार को तलब किया था।

## लखनऊ में भारत और वेस्टइंडीज टी२० का क्रेज: वीआईपी लाउंज का टिकट खरीदने में उड़ सकती कई लोगों की मंथली सैलरी

लखनऊ। भारत और वेस्टइंडीज के बीच ६ अक्टूबर को होने वाले पहले टी२० मुकाबले को लेकर राजधानी लखनऊ में क्रिकेट का रोमांच बढ़ने लगा है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने

प्रेस वार्ता में यूपीसीए के सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने बताया कि मैच के सफल आयोजन के लिए सभी जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि दर्शकों के लिए टिकट की शुरुआती कीमत ३६६ रुपये रखी गई है। वहीं,



वाले इस मुकाबले की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। शनिवार, १६ सितंबर को मैच के टिकट लांच किए गए। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) की ओर से आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। टिकट लांचिंग समारोह के दौरान

सबसे महंगा टिकट साउथ वीआईपी लाउंज १ एवं २ का है, जिसकी कीमत १३,५०० रुपये निर्धारित की गई है। यूपीसीए के कोषाध्यक्ष सचिन आनंद शुक्ला ने बताया कि भारत-वेस्टइंडीज टी२० मुकाबले के टिकटों की ऑनलाइन बिक्री शुरू हो चुकी

है। क्रिकेट प्रशंसक क्पेजतपबज ऐप (Zomato) के जरिए टिकट खरीद सकते हैं। अ नलाइन बिक्री शनिवार शाम से शुरू की गई। यूपीसीए के मुताबिक मैच को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है और बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमियों के इकाना स्टेडियम पहुंचने की उम्मीद है। यूपीसीए की मीडिया समिति के चेयरमैन मोहम्मद फहीम ने कहा कि एसोसिएशन एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मुकाबले की सफल मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने उम्मीद जताई कि लखनऊ के क्रिकेट प्रशंसकों को मैच के दौरान शानदार अनुभव मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में इकाना स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों का आयोजन जारी रहेगा। वहीं, इकाना स्पोर्ट्स सिटी के सीएमडी उदय सिन्हा ने बताया कि मैच को लेकर स्टेडियम में तैयारियां तेजी से चल रही हैं। दर्शकों को मैच के दौरान बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

## ४० लाख की ब्राउन शुगर के साथ दो गिरफ्तार पलिया-दुधवा रोड पर रात में पुलिस ने की कार्रवाई, १८६.५७ ग्राम मादक पदार्थ बरामद

पलियाकलां-खीरी। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत पलिया कोतवाली पुलिस ने आज

है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ख्याति गर्ग के निर्देशन में पलिया कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शिवाजी दुबे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पलिया-



फिर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शिवाजी दुबे अब १६ अभियुक्तों को मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार करके जेल भेज चुके हैं। आज रविवार की सुबह दो युवकों को गिरफ्तार किया गया

दुधवा रोड पर स्थित कर्नल बिली अर्जुन सिंह स्मृति द्वार से पहले पलिया के पास से नगर के मोहल्ला किसान प्रथम निवासी कुनाल गुप्ता पुत्र विशाल गुप्ता एवं मोहल्ला रंगरेजान द्वितीय निवासी अनुराग कश्यप पुत्र

रामगोपाल को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से १८६.५७ ग्राम ब्राउन शुगर (स्मैक) बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब ४० लाख रुपये बताई गई है। प्रभारी निरीक्षक शिवाजी दुबे ने बताया कि कुनाल के पास से ६३.८८ ग्राम और अनुराग के पास से ६२.६६ ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई है। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा ८६२१ के तहत मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गयी है। उन्होंने बताया कि अनुराग कश्यप का अपराधिक इतिहास भी रहा है। उसके खिलाफ पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट व गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में महिला उपनिरीक्ष निशा शुक्ला, हेड कांस्टेबल जयप्रकाश, कांस्टेबल अतुल त्रिपाठी, शनि यादव, रोहित भडाना एवं रामभूल शामिल रहे।

## सीएमओ ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेलों का किया औचक निरीक्षण



जायजा लिया। उन्होंने उपस्थित डॉक्टरों व स्टाफ को निर्देश दिया कि मेले में आने वाले किसी भी मरीज को कोई असुविधा न हो और सभी को बेहतर इलाज मिले। बता दें कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का उद्देश्य हर जरूरतमंद तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है। इस मेले में मरीजों को निःशुल्क ओपीडी, मुफ्त दवाएं, मातृ-शिशु स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण और परिवार नियोजन परामर्श जैसी कई महत्वपूर्ण सेवाएं दी जाती हैं। इसके साथ ही, मेले में गोल्डन कार्ड (आयुष्मान कार्ड) बनाने, और टीबी, मलेरिया व अन्य मौसमी बीमारियों की निःशुल्क जांच एवं उपचार की सुविधा भी एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाती है।

लखीमपुर खीरी। रविवार को मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले के आयोजन के दृष्टिगत मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. संतोष गुप्ता ने नगरीय स्वास्थ्य केंद्र निर्मल नगर और नौरंगाबाद का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत परखी और कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सीएमओ डॉ. गुप्ता ने निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में साफ-सफाई, दवाओं की उपलब्धता और मरीजों के पंजीकरण व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने उपस्थित डॉक्टरों व स्टाफ को निर्देश दिया कि मेले में आने वाले किसी भी मरीज को कोई असुविधा न हो और सभी को बेहतर इलाज मिले। बता दें कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का उद्देश्य हर जरूरतमंद तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है। इस मेले में मरीजों को निःशुल्क ओपीडी, मुफ्त दवाएं, मातृ-शिशु स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण और परिवार नियोजन परामर्श जैसी कई महत्वपूर्ण सेवाएं दी जाती हैं। इसके साथ ही, मेले में गोल्डन कार्ड (आयुष्मान कार्ड) बनाने, और टीबी, मलेरिया व अन्य मौसमी बीमारियों की निःशुल्क जांच एवं उपचार की सुविधा भी एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाती है।

## भारतीय अंडर-१९ टीम ऑस्ट्रेलिया को सात रनों से हराया

नई दिल्ली। यशबर्धन चौहान (५४/दो विकेट) रन, अन्वय द्रविड़ (३८), आर्यवीर सहवाग (२८) शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारतीय अंडर-१९ टीम बारिश प्रभावित पहले यूथ वनडे में ऑस्ट्रेलिया अंडर-१९ टीम को सात रनों से शिकस्त दी। १८३ रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया के लिए नील पटेल और हेडन बारबुलोविक की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए ५८ रन जोड़कर अच्छी शुरुआत की। सातवें ओवर में चौहान ने हेडन (४५) रन को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद ११वें ओवर में चौहान ने नील पटेल (४०) को भी अपना शिकार बना लिया। जेड होलिक (२५) रन बनाकर आउट हुये। कप्तान जैक स सनेक ने २७ गेंदों में छह चौके और तीन छक्के लगाते हुए (५५) रनों की आतिशी पारी खेलते हुए अपनी टीम को जीत दिलाने का प्रयास किया। १६वें ओवर की पांचवीं गेंद पर चिगुरपति वेंकटा ने स सनेक को आउट कर ऑस्ट्रेलिया के मैच जीने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आखिरी ओवरों में भारतीय गेंदबाजों बेहतरीन प्रदर्शन के आगे ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज सात विकेट पर १७५ रन ही बना सके और उनकी टीम मुकाबला सात

रनों से हार गई। इससे पहले आज यहां अ स्ट्रेलिया की अंडर-१९ टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी भारत की अंडर-१९ टीम ने यशबर्धन चौहान ने ३४ गेंदों में पांच चौके और दो छक्के उड़ाते हुए (५४) रनों की



अर्धतशकीय पारी खेली। अन्वय द्रविड़ ने १८ गेंदों में दो चौके और तीन छक्के लगाते हुए (३८) रन बनाये। आर्यवीर सहवाग ने २६ गेंदों में पांच चौके जड़ते हुए (२८) रन बनाये। अन्वय द्रविड़ और यशबर्धन चौहान के बीच ३४ गेंदों में ६६ रनों की साझेदारी हुई। वहीं, कुशाग्र ओझा (१६), कप्तान लक्ष्य रायचंदानी (१५) और अर्जुन राजपूत (१५) रनों की पारियों का योगदान दिया। बारिश के कारण मैच को २०-२० ओवरों का कर दिया गया था। भारतीय टीम ने छह विकेट पर १८२ रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्पेंसर ग्रीन और एली ब्रेन को दो-दो विकेट मिले।

## पानी भरे गे में डूबने से तीन किशोरों की मौत

बाराबंकी। बाराबंकी में कुर्सी थाना क्षेत्र के बैना टीकाहार गांव में रविवार शाम दर्दनाक हादसा हो गया। निर्माणाधीन फैक्टरी परिसर में खोदे गए गहरे गड्ढे में बारिश का पानी भरा था। इसी पानी में नहाने गए तीन किशोर डूब गए। हादसे में दो किशोरों की मौत हो

गुड्डू का बेटा दुर्गेश (१५) और धर्मराज का बेटा दिव्यांश (१२) गड्ढे में भरे पानी में नहाने पहुंचे थे। कुछ अन्य बच्चे भी आसपास मौजूद थे। नहाते समय तीनों किशोर गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। उन्हें डूबता देखकर आसपास मौजूद बच्चों ने



गई, जबकि तीसरा पानी में लापता है। सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से लापता किशोर की तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक गांव के बाहर एक फैक्टरी की चहारदीवारी का निर्माण चल रहा है। परिसर में मिट्टी भराई के काम के लिए करीब १०० मीटर व्यास का गड्ढा खोदा गया था। पिछले दिनों हुई बारिश के कारण इसमें काफी पानी भर गया था। रविवार शाम गांव निवासी रामशंकर का बेटा सुमित (१५),

शोर मचाया। आवाज सुनकर फैक्टरी में काम कर रहे मजदूर मौके पर पहुंचे और पानी में उतरकर सुमित व दुर्गेश को बाहर निकाला। हालांकि तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। तीसरे बालक दिव्यांश का पता न चलने पर कुर्सी पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद ली। रात में लाइट की व्यवस्था कर तलाश शुरू की गई, जिसके बाद दिव्यांश का शव भी गड्ढे से बरामद कर लिया गया। हादसे की सूचना पर एसडीएम फतेहपुर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। तीनों बच्चों की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पुलिस मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है।

## आकाश आउट, दीपिका से भी किनारा! अब ईशान आनंद के हाथों में होगी जिम्मेदारी? मायावती का सबसे बड़ा फैसला

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने अपने परिवार के सदस्यों की पार्टी में राजनीतिक भूमिका को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक उन्होंने अपने भाई आनंद कुमार के बेटों आकाश आनंद और ईशान आनंद को पार्टी में राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं देने की बात कही है। वहीं, भाई की बेटी दीपिका आनंद को भविष्य में जरूरत पड़ने पर पार्टी की जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना जताई गई है। मायावती ने अपने हालिया बयान में स्पष्ट किया कि आनंद कुमार के दोनों बेटों आकाश और ईशान को बसपा में किसी छोटे या बड़े राजनीतिक पद पर जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। उन्होंने परिवार के अन्य सदस्यों को राजनीतिक लाभ देने के बजाय पार्टी और बहुजन समाज के हित को प्राथमिकता देने की बात कही है। आकाश आनंद को लेकर मायावती पहले भी पार्टी स्तर पर कार्रवाई कर चुकी हैं। सितंबर में

उन्हें पार्टी की जिम्मेदारियों से अलग किया गया था। दीपिका आनंद को लेकर मायावती का रुख आकाश और ईशान से अलग रहा है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने कहा था कि अगर आनंद



कुमार को संगठनात्मक काम में मदद की जरूरत होती है तो उनकी बेटी दीपिका मदद कर सकती हैं। उनकी ईमानदारी और कार्यक्षमता के आधार पर भविष्य में उन्हें पार्टी में जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना भी जताई गई थी। हालांकि, दीपिका को पार्टी में कोई नई औपचारिक जिम्मेदारी दिए जाने की अंतिम घोषणा अभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है। २३ सितंबर की प्रस्तावित बैठक में उनके राजनीतिक भविष्य को

लेकर चर्चा होने की रिपोर्टें हैं। मायावती ने २३ सितंबर को पार्टी के पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई है। रिपोर्टों के मुताबिक बैठक में आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों, प्रत्याशियों की समीक्षा और पार्टी के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होनी है। दीपिका को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होने की संभावना बताई गई है। मायावती ने अपने फैसले को बसपा संस्थापक कांशीराम की राजनीतिक सोच से जोड़ते हुए कहा है कि उन्होंने अपने परिवार को राजनीतिक लाभ से दूर रखने की नीति अपनाई। उन्होंने बाबा साहेब ड. भीमराव अंबेडकर के एक पुराने पत्र का भी हवाला देते हुए सार्वजनिक संपत्ति और जवाबदेही से जुड़े उनके विचारों का उल्लेख किया। मायावती ने यह भी कहा कि उनके लिए पूरा बहुजन समाज ही परिवार है और पार्टी का उद्देश्य बहुजन समाज को राजनीतिक रूप से मजबूत करना है।

## लखनऊ विश्वविद्यालय के कैलाश हॉस्टल की मेस पर सवाल, ४० हजार फीस के बाद खाने में कीड़े-बाल मिलने का आरोप

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के कैलाश छात्रावास में मेस की बदहाल व्यवस्था को लेकर छात्रों का गुस्सा शनिवार को फूट पड़ा। छात्रों ने आरोप लगाया कि करीब ४० हजार रुपये लेने के बावजूद उन्हें खाने में आए दिन कीड़े और बाल मिल रहे हैं। बर्तन ठीक से नहीं धोए जाते और कई बार जूठे बर्तनों में खाना परोसा जाता है। रसोई परिसर में कई दिनों से कचरा जमा होने का भी आरोप है। छात्रों ने मेस कर्मचारियों पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। मेस की समस्याओं को लेकर छात्राएं पहले छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो. अमिता कनौजिया से मिलने पहुंचीं। छात्रों का आरोप है कि वहां उनकी शिकायत गंभीरता से नहीं सुनी गई और उन्हें हड़काया गया। इससे नाराज छात्रों ने कुलपति कार्यालय का घेराव कर दिया। सूचना पर चीफ प्रॉक्टर प्रो. राकेश द्विवेदी, चीफ प्रोवोस्ट प्रो. आशीष अवस्थी और प्रो. ओपी शुक्ला मौके

पर पहुंचे। अधिकारियों ने छात्रों की कुलपति से मुलाकात कराई। छात्रों ने कुलपति से शिकायत की। छात्र नेता एवं समाजवादी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभिषेक श्रीवास्तव "बाबू" ने



कहा कि छात्रों और मेस की समस्या बेहद गंभीर है। छात्र-छात्राओं की बात गंभीरता से सुनी जानी चाहिए और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ४० हजार रुपये लेने के बाद भी खाने में कीड़े और गंदगी की लगातार शिकायतें सामने आना गंभीर मामला है। न्याय न मिला तो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस दौरान हिमांशु यादव, अक्षय वर्मा, धीरज यादव, अजीतेंद्र, रुस्तम, अमन दुबे और विराट आदि छात्र मौजूद रहे।

## महिला थाने के परिवार परामर्श केन्द्र पर सुलह से ११ जोड़े दम्पतियों की हुई विदाई

लखीमपुर-खीरी। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप पुलिस अधीक्षक डॉ. ख्याति गर्ग के निर्देशन में थानाध्यक्ष महिला थाना बबिता पटेल द्वारा काउंसलर श्रीमती नीति गुप्ता, सुश्री कुसुम गुप्ता, कय्यूम जरवानी के द्वारा पारिवारिक विवादों के २२ मामलों में सुलह कराके ११ जोड़े पति पत्नी की विदाई कराके सहायनीय कार्य किया गया है। बताते चलें कि जनपद मुख्यालय पर पुलिस अधीक्षक डॉ. ख्याति गर्ग के दिशा निर्देशन में महिला थाने के परिवार परामर्श केन्द्र पर थानाध्यक्ष श्रीमती बबिता पटेल व काउंसलर श्रीमती नीति गुप्ता, सुश्री कुसुम गुप्ता, कय्यूम जरवानी द्वारा दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा के उत्पीड़न, साझी गृहस्थी में निवास को लेकर उत्पन्न होने वाली समस्याओं के २२ मामलों में सुलह समझौता का

प्रयास किया गया, जिसमें से ११ जोड़े पति-पत्नी की विदाई कराई गई है, ०८ मामले ऐसे थे जिनमें पति-पत्नी में अत्यधिक मनमुटाव



था जिसमें पक्षकारों को सोचने का समय दिया गया है, ०३ मामलों में जिसमें सुलह प्रयास सार्थक नहीं हुआ, इस अवसर पर महिला थाने की उपनिरीक्षक दिनेश मणि पाण्डेय, महिला आरक्षी सुमन लता, रेखा गौड़ द्वारा काफी सहयोग किया गया है, सुलह समझौता के समय पक्षकारों के परिवारीजन भी उपस्थित रहे हैं।

## बिजली और पानी की व्यवस्था का अभाव झाड़ियों और गंदगी से घिरा अंतिम संस्कार स्थल

लखीमपुर खीरी। विकास खण्ड बांकेगंज की ग्राम पंचायत ग्रंट नंबर १० स्थित श्मशान घाट इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। अंतिम विदाई के इस पवित्र और महत्वपूर्ण स्थल पर मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। श्मशान घाट परिसर पूरी तरह से घनी झाड़ियों, घास-फूस और गंदगी से घिरा हुआ है, जिससे यहाँ आने वाले ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जिम्मेदार अधिकारियों और ग्राम पंचायत प्रशासन से मौके का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द दुरुस्त कराने की मांग उठाई है। सामने आई तस्वीरों और स्थानीय निवासियों के अनुसार, श्मशान घाट परिसर की नियमित सफाई न होने के कारण यहाँ बड़ी-बड़ी झाड़ियाँ और खरपतवार उग आए हैं। पूरा परिसर

एक जंगल जैसा नजर आने लगा है। स्थिति यह है कि अंतिम संस्कार में शामिल होने आने वाले लोगों को झाड़ियों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे हमेशा जहरीले जीव-जंतुओं का डर बना रहता है। परिसर के अंदर जर्जर और अधूरे निर्माण की संरचनाएं भी दिखाई दे रही हैं, जो इसकी उपेक्षा की कहानी खुद बयां कर रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार के दौरान सबसे ज्यादा जरूरत बिजली और पानी की होती है। लेकिन दुर्भाग्यवश, यहाँ न तो पीने के पानी (पेयजल) की कोई उचित व्यवस्था है और न ही रोशनी के लिए बिजली के इंतजाम हैं। यदि शाम या रात के समय किसी का अंतिम संस्कार करना पड़े, तो अंधेरे के कारण स्थिति और भी विकट हो जाती है। स्थानीय ग्रामीणों ने रोष व्यक्त करते

हुए कहा कि अंतिम संस्कार स्थल जैसी संवेदनशील और सार्वजनिक सुविधा की इस तरह उपेक्षा बेहद निंदनीय है। ग्रामीणों ने संबंधित उच्चाधिकारियों से मांग की है कि श्मशान घाट का स्थलीय निरीक्षण किया जाए। परिसर की तत्काल सफाई करवाकर झाड़ियों को साफ किया जाए। बिजली, पानी (हैण्डपम्प/पेयजल) और अन्य जरूरी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था कराई जाए। श्मशान घाट की देखरेख और नियमित रखरखाव के लिए किसी की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय की जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि जिम्मेदार विभाग और ग्राम पंचायत इस मामले को गंभीरता से लें और जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई करें, ताकि आम जनता को इस परेशानी से मुक्ति मिल सके।

## ग्राम पंचायत कुकरा में विधायक रोमी साहनी के प्रयासों से बदली सड़क की सूरत, ग्रामीणों को मिली राहत।



कुकरा खीरी। ब्लॉक बांकेगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुकरा की अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रमुख सड़कों की खस्ताहाल स्थिति से अब स्थानीय निवासियों और राहगीरों को जल्द ही मुक्ति मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री त्वरित कार्य योजना के तहत क्षेत्रीय विधायक माननीय रोमी साहनी के विशेष प्रयासों से ५०५ मीटर इंटरल किंग सड़क का निर्माण कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया है। ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण सड़कें गुलशन चमन चौराहे से बाजार तक और नूरी मेडिकल स्टोर से भीरा रोड तक लंबे समय से बदहाल स्थिति में थीं। स्थानीय ग्राम प्रधान द्वारा अब तक इस ओर ध्यान न दिए जाने के कारण लोगों को आवागमन में भारी कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ता था। रविवार को नूरी मेडिकल स्टोर से भीरा रोड की तरफ लगभग २५० मीटर हिस्से में इंटरल किंग टाइल्स लगाने का काम शुरू हो गया। वर्षों पुरानी समस्या का निस्तारण होने और निर्माण कार्य शुरू होने पर मोहल्लेवासियों ने राहत की सांस ली तथा विधायक रोमी साहनी का आभार व्यक्त किया। कार्य के शुभारंभ के अवसर पर भाजपा नेता शेर अली खान, सुरेंद्र पाल मिश्रा, राजकुमार सक्सेना, समीम खान, डॉ. अब्दुल मतीन खान, रोहतास खान, उपदीप प्रजापति, शंकर प्रजापति, शादाब खान, चुन्ना इंदरीसी सहित कई गणमान्य नागरिक और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने पारदर्शी व गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने का भरोसा जताया।

# यूपी में नए पैकेट में पुराना सामान बेचने पर लगेगी रोक, खाद्य उत्पादों की असली मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखना अनिवार्य

लखनऊ। प्रदेश में बिकने वाले पैकड खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को धोखे से बचाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। नए निर्देशों के अनुसार, अब यूपी की भौगोलिक सीमाओं के भीतर पैक किए जाने वाले सभी खाद्य उत्पादों के पैकेट पर वास्तविक विनिर्माण तिथि साफ-साफ अंकित करना अनिवार्य होगा। अब कोई भी कंपनी या रीपैकर, सामग्री के पैक होने वाले दिन को विनिर्माण तिथि के स्थान पर प्रदर्शित नहीं कर सकेगा। आयुक्त द्वारा यह कड़ा निर्णय हाल ही में खाद्य विनिर्माण इकाइयों के विशेष औचक निरीक्षणों के बाद लिया गया है। जांच में पाया गया कि कई कंपनियां खाद्य पदार्थ का उत्पादन पहले कर लेती थीं और उसे महीनों तक कोल्ड स्टोरेज या गोदामों में भण्डारित रखती थीं। बाद में जब उसे छोटे पैकेटों में पैक किया जाता था, तो उस पर वास्तविक उत्पादन तिथि के बजाय

पैकिंग के दिन की तारीख डाल दी जाती थी, जिससे पुराना माल भी नया लगने लगता था। विभागीय छानबीन में यह बात भी प्रकाश में आई है कि कुछ मामलों में रीलेबलर और रीपैकर केवल पैकिंग की तारीख लिखकर बाजार में माल



सप्लाई कर रहे थे। ऐसी स्थिति में आम उपभोक्ताओं को यह कभी पता ही नहीं चल पाता था कि संबंधित खाद्य पदार्थ वास्तव में कब निर्मित या प्रसंस्कृत हुआ था। इससे उत्पाद के वास्तविक भण्डारण काल (शेल्फ लाइफ) और उसकी शुद्धता व गुणवत्ता के संबंध में उपभोक्ताओं के सामने हमेशा असमंजस और भ्रम की स्थिति बनी रहती थी। शासन ने अब इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य

विशेषज्ञों के अनुसार, किसी भी खाद्य पदार्थ की एक निर्धारित उपयोग अवधि यानी शेल्फ लाइफ होती है, जो उसके वास्तविक विनिर्माण या प्रसंस्करण के दिन से ही शुरू हो जाती है। समय बीतने के साथ खाद्य पदार्थ के पोषक तत्वों और उसकी गुणवत्ता में स्वतः कमी आने लगती है। यदि पुराने उत्पाद को कई महीनों बाद नए पैकेट में डालकर केवल पैकिंग की तारीख चमका दी जाए, तो उपभोक्ता को धोखा होता है। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब ऐसे पुराने खाद्य उत्पादों का उपयोग किसी अन्य खाद्य सामग्री या होटल-रेस्टोरेंट की रसोई में अवयव के रूप में किया जाता है, जिससे फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है। आयुक्त ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, २००६ में निहित प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि यह व्यवस्था जन स्वास्थ्य, पारदर्शिता और खाद्य सुरक्षा (ट्रेसबिलिटी) को मजबूत करने के लिए लागू की गई है।

# ‘समुक’ में रजत कपूर की एंट्री की चर्चा

मुम्बई। अक्षय कुमार और विपुल अमृतलाल शाह की साइंस-फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म ‘समुक’ में अभिनेता एवं फिल्मकार रजत कपूर की एंट्री की चर्चा है। कहा जा रहा है कि रजत कपूर फिल्म में अहम किरदार निभा सकते



हैं। कनिष्क वर्मा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म का निर्माण विपुल अमृतलाल शाह अपने बैनर सनशाइन पिक्चर्स के तहत कर रहे हैं, जबकि आशिन ए. शाह इसके सह-निर्माता हैं। फिल्म की शूटिंग फिलहाल यूके में चल रही है। ‘समुक’ को बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है। फिल्म में साइंस फिक्शन के साथ एक्शन और सर्वाइवल का रोमांच देखने को मिलेगा। हालांकि, निर्माताओं ने अभी तक कहानी और किरदारों को लेकर विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है। रजत कपूर अपने

सहज और प्रभावशाली अभिनय के लिए जाने जाते हैं। ‘मॉनसून वेडिंग’, ‘भेजा फ्राय’, ‘कपूर एंड संस’, ‘मुल्क’, ‘श्यम २’ और ‘गहराइयां’ जैसी फिल्मों में उन्होंने अलग-अलग भूमिकाएं निभाई हैं। वह ‘रात अकेली है। द बंसल मर्डर्स’ और ‘मैं वापस आऊंगा’ में भी नजर आए हैं। बताया जा रहा है कि ‘समुक’ में रजत कपूर का किरदार कहानी के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। फिल्म अक्षय कुमार और विपुल अमृतलाल शाह की १३ वर्ष बाद साथ में वापसी है। यह प्रोजेक्ट दो वर्ष से अधिक समय से विकास के दौर में है और इसे सिनेमाघरों में प्रदर्शित करने के लिए बड़े स्तर पर तैयार किया जा रहा है।

हमारे अन्य प्रतिनिधि

संजय बाजपेई

सीतापुर

मो.9935160370

प्रियंका त्रिपाठी

नई दिल्ली

विधिक सलाहकार

सुरेश नारायण मिश्र

क्षेत्रीय सम्पादक

सौरभ कुमार, बिहार

मो.09386075289

मो० अरशद

ब्यूरो चीफ

मऊ

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा साईं आफसेट प्रिन्टर्स, 40 वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी 2/379 रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ0प्र0 से प्रकाशित। आर.एन.आई UPHIN/2010/32566 सम्पादक आरती पाण्डेय मो.9415087228 9889745884. 9807059191. 9026560178 Email- adbhutsamachar @yahoo.in adbhut\_samachar @rediffmail.com सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

# बिहार की चार हस्तियों को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

बिहार की चार फिल्मी हस्तियों को वर्ष २०२४ के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बिहार के लिए ७२वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह खास होने जा रहा है। बिहार से जुड़ी चार फिल्मी हस्तियों अभिनेता संजय मिश्रा, निर्देशक कमलेश के. मिश्र, निर्माता मिंटी मिश्रा और फिल्म समीक्षक संजीव श्रीवास्तव को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू २२ सितंबर को गुजरात के एकता नगर (केवाड़िया) में आयोजित समारोह में पुरस्कार प्रदान करेंगी। दरभंगा निवासी अभिनेता संजय मिश्रा को फिल्म ‘भक्षक’ में बेहतरीन अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का रजत कमल प्रदान किया जाएगा। ‘भक्षक’ की कहानी चर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड से प्रेरित है। गोपालगंज निवासी

निर्देशक कमलेश के. मिश्र और निर्माता मिंटी मिश्रा को फिल्म ‘काकोरी’ के लिए सर्वश्रेष्ठ जीवनी परक / ऐतिहासिक



पुनर्निर्माण/संकलन फिल्म का रजत कमल प्रदान किया जाएगा। देशभक्ति पर आधारित यह फिल्म १६२५ के ऐतिहासिक ‘काकोरी ट्रेन एक्शन’ के शताब्दी वर्ष पर काकोरी के अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित है। फिल्म में

काकोरी की ऐतिहासिक घटना और उससे जुड़े स्वतंत्रता सेनानियों के शौर्य, संकल्प और उनके अमिट योगदान को रेखांकित किया गया

है। कमलेश के. मिश्र की फिल्म को पहले भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। उनकी फिल्म ‘मधुबनी: द स्टेशन ऑफ कलर्स’ के लिए गैर-फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कथन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था।

फिल्मकार कमलेश मिश्र की पहली निर्देशित फीचर फिल्म ‘आजमगढ़’ है, जिसमें पंकज त्रिपाठी ने मुख्य नेगेटिव भूमिका निभाई है। यह फिल्म आतंकवाद के विषय पर आधारित है। अपनी फिल्मों में विशेष दृष्टिकोण से इतिहास और रिसर्च को प्रमुख स्थान देते हैं। हाल ही में उन्होंने २०२० के दिल्ली दंगों पर ‘दिल्ली दंगे जलने और दोषारोपण की कहानी’ ( दिल्ली राइट्स- ऑटेल ऑफ बर्न एंड ब्लेम) डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जो तब काफी चर्चित हुई थी। उनकी पहली शोर्ट फिल्म “किताब” ने वैश्विक ख्याति अर्जित की। काकोरी के निर्माता जसविंदर सिंह दिल्ली से और मिंटी मिश्रा बिहार के गोपालगंज की हैं। यह फिल्म उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के सहयोग से बनी है। बिहार के दरभंगा के रहने वाले संजय मिश्रा देश के प्रसिद्ध अभिनेता हैं।

# द रेवोल्यूशनरीज के लिए रोहित सराफ ने की १५ महीने की ट्रेनिंग



अभिनेता रोहित सराफ ने अपनी वेब सीरीज ‘द रेवोल्यूशनरीज’ में स्वतंत्रता सेनानी सचिंद्रनाथ सान्याल का किरदार निभाने के लिए करीब १५ महीने तक कड़ी ट्रेनिंग की। रोहित ने बताया कि किरदार के लिए उन्होंने करीब तीन महीने तक मल्लखंब और कुश्ती की भी ट्रेनिंग ली। निर्देशक निखिल आडवाणी से पहली मुलाकात के दौरान उन्हें अपने शरीर को ह लीवुड अभिनेता ब्रैंड पिट के ‘फाइट क्लब’ वाले लुक जैसा बनाने के लिए कहा गया था। रोहित ने कहा कि वह पहले से फिट थे, लेकिन ‘फाइट क्लब’ में ब्रैंड पिट जैसा शरीर उनके पास नहीं था। इसलिए निर्देशक की कल्पना के मुताबिक शरीर तैयार करना उनके लिए बड़ी चुनौती थी। उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग काफी कठिन और थकाने वाली थी तथा वह नियमित रूप से ट्रेनिंग के वीडियो निखिल आडवाणी को भेजते थे। अभिनेता के अनुसार, ट्रेनिंग के दौरान उनके शरीर के साथ-साथ उनके चलने-फिरने का तरीका भी धीरे-धीरे बदलने लगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि पर बनी ‘द रेवोल्यूशनरीज’ में रोहित सराफ के अलावा भुवन बाम, प्रतिभा रांटा, गुरफतेह पीरजादा, जेसन शाह, पाओली डैम और तोता राय चौधरी भी हैं। सीरीज अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है।

समाचार पत्र में छपी समस्त प्रकार की खबरों एवं लेखों का स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। समाचार पत्र में छपी खबर एवं लेख पत्रकारों के अपने निजी विचार हैं। समाचार पत्र से जुड़े समस्त पत्रकारों के पद अवैतनिक हैं। और वह सब स्वतंत्र पत्रकार हैं। प्रकाशक/सम्पादक